

जलवायु परिवर्तन की चपेट में चैन्नई

प्रमोद भार्गव



86 लाख की आबादी वाला शहर चैन्नई लगभग जलमग्न है। चैन्नई के अलावा नेल्लोर, चित्तूर, प्रकाशम, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, विल्लूपुरम और पुडुचेरी में भी प्रकृति का यही रौद्र रूप देखने में आ रहा है। इसके पहले हम जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, लद्दाख और 2005 में मुंबई में भी यही स्थिति देख चुके हैं। संभवतः एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं।

इस बारिश ने सौ साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। औसत से तीन गुना अधिक बारिश हुई। सभी शिक्षण संस्थान तो बंद हैं ही, एक हजार से ज्यादा दफ्तर और कारखाने भी बंद हैं। नगर की 50 लाख से भी अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है। सेना के तीनों अंगों की मदद के बावजूद लोगों को घरेलू सामान के जुगाड़ से नाव बनाकर, ज़िन्दगी को जोखिम में डालकर किनारे तलाशने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 269 लोगों की मृत्यु का बयान दिया है। यह प्रलयकारी संकट कुदरती तो है,

लेकिन इसके तांडव का सबब अनियंत्रित औद्योगिक विकास और विस्तार लेता अनियोजित शहरीकरण भी है जिसके चलते मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं के संकट से धिरता जा रहा है।

तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मानसून के चलते इन दिनों तेज़ बारिश होती है। हिमालय के छोर से प्रवाहित ठंडी हवाएं बंगाल की खाड़ी से जल का शोषण कर नमी पाती हैं और दिसंबर से मार्च के बीच प्रायद्वीपीय भारत में बरसात की वजह बनती हैं। इस मर्तबा हैरानी में डालने वाली बात यह रही कि एक महीने के भीतर ही इस इलाके में उतनी बारिश हो चुकी है, जो चार महीनों में होती है। 30 नवंबर और एक दिसंबर के दरमियान ही करीब 1088 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे चैन्नई की सभी 35 झीलें और ताल-तलैया उफान पर आ गए। नतीजतन इस आफत की बारिश ने देश के चौथे बड़े शहर को पानी-पानी कर दिया।

आफत की यह बारिश इस बात की चेतावनी है कि

हमारे नीति-नियंता दूरदृष्टि से काम नहीं ले रहे हैं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मसलों के परिप्रेक्ष्य में चिंतित नहीं हैं। 2008 में जलवायु परिवर्तन के अंतरसरकारी समूह ने रिपोर्ट दी थी कि धरती पर बढ़ रहे तापमान के चलते भारत ही नहीं दुनिया भर के वर्षा चक्र में बदलाव आने वाले हैं। इसका सबसे ज्यादा असर महानगरों पर पड़ेगा। इस लिहाज़ से शहरों में जल प्रबंधन व निकासी के असरकारी उपायों की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के मिलने के तत्काल बाद केंद्र की तत्कालीन संप्रग्रं सरकार ने राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएं तैयार करने की हिदायत दी थी। लेकिन देश के किसी भी राज्य ने इस अहम सलाह पर गौर नहीं किया। इसी का नतीजा है कि हम जल त्रासदियां भुगतने को विवश हो रहे हैं।

यही नहीं शहरीकरण पर अंकुश लगाने की बजाय ऐसे उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे शहरों की आबादी बढ़ती है। ध्यान रहे कि 2031 तक भारत की शहरी आबादी 20 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। जो देश की कुल आबादी की 40 प्रतिशत होगी।

वैसे धरती के गर्म और ठंडे होते रहने का क्रम उसकी प्रकृति का हिस्सा है। इसका प्रभाव पूरे जैवमंडल पर पड़ता है, जिससे जैविक विविधता का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन कुछ वर्षों से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज़ हुई है। इससे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है। यह स्थिति प्रकृति में अतिरिक्त मानवीय दखल से पैदा हो रही है। इसलिए इस पर नियंत्रण संभव है। पैरिस में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो सम्मेलन चल रहा है, वह भी धरती के तापमान को नियंत्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चैन्सेलर की इस जल त्रासदी को ग्लोबल वार्मिंग का परिमाण मान रहे हैं। इस नाते उन्होंने विश्व जलवायु सम्मेलन का ध्यान भी इस ओर खींचा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन समिति के वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि ‘तापमान में वृद्धि न केवल मौसम का मिजाज बदल रही है, बल्कि कीटनाशक दवाओं से निष्प्रभावी रहने वाले विषाणुओं-जीवाणुओं, गंभीर बीमारियों, सामाजिक संघर्षों और व्यक्तियों

में मानसिक तनाव बढ़ाने का काम भी कर रही है।’

दरअसल, पर्यावरण के असंतुलन के कारण गर्मी, बारिश और ठंड का संतुलन भी बिगड़ता है। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य और कृषि की पैदावार व फसल की पौष्टिकता पर पड़ता है। यदि मौसम में आ रहे बदलाव से बीते तीन-चार साल के भीतर घटी प्राकृतिक आपदाओं और संक्रामक रोगों की पड़ताल की जाए तो वे हैरानी में डालने वाले हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव से लू लगने जैसी समस्याओं, तथा दिल व सांस सम्बंधी रोगों से मृत्यु दर में इजाफा हो सकता है। पश्चिमी युरोप में 2003 में दर्ज रिकॉर्ड उच्च तापमान से 70 हजार से अधिक मौतों का सम्बंध था।

बाढ़ के दूषित जल से डायरिया व आंख के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। भारत में डायरिया से हर साल करीब 18 लाख लोगों की मौत हो रही है। इसी दूषित जल से डॅगू और मलेरिया के मच्छर कहर ढाते हैं। तथा है बाढ़ थमने के बाद, बाढ़ प्रभावित शहरों को विविध संकटों का सामना करना होगा।

चैन्सेलर की वर्तमान मुसीबत की वजह कम समय में ज्यादा बारिश होना तो है ही, जल निकासी के इंतज़ाम नाकाफी होना भी है। दरअसल औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास के चलते शहर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, गांव और ताल-तलैयों को निगलते जा रहे हैं। इस कारण जहां जल संग्रहण का क्षेत्र कम हो रहा है, वहीं अनियोजित शहरीकरण से बरसाती पानी के रास्ते बंद हो रहे हैं। समुद्र तटीय महानगर होने के कारण चैन्सेलर का बड़ा क्षेत्र समुद्र तल के बराबर या उससे नीचे है। लिहाज़ा करीब दो तिहाई शहर की 481 बस्तियां पानी में डूब गईं। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सड़कें व फ्लाई ओवर तक डूब गए। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी जलमग्न हैं। एक हजार से ज्यादा दफ्तर और कारखानों में पानी भर गया है।

इतने बढ़े क्षेत्र में जल भराव का कारण चैन्सेलर के विकास हाइड्रोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित प्लान के अनुसार नहीं होना भी है।

चैन्सेलर आईटी और ऑटो कंपनियों का बड़ा केंद्र है।

अधिकतर कंपनियों के कार्यालयों में पानी भरा है। फोर्ड, डेमलर, निसान, टीवीएस, हुंडई, रेनो और अशोक लैलेंड के कारखाने यहीं हैं। फोर्ड संयंत्र फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 3.4 लाख इंजन और 2 लाख वाहन है। किंतु पानी भर जाने से उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी और कंपनी समय पर अपने उत्पाद उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा पाएगी। वैनर्इ में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली टीसीएस, इफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसी कंपनियां भी हैं। इनका भी कारोबार ठप है। इस कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज होने वाली है। इंडिया सीमेंट कंपनी भी ऐसे ही हालातों से दो-चार हो रही है। इन कंपनियों में 15 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान

लगाया जा रहा है। नगरीय संरचना को 8.5 हजार करोड़ की हानि पहुंचने का अंदाजा है। फौरन राहत के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ की मांग की थी, इसके बदले में 940 करोड़ की आर्थिक सहायता तत्काल केंद्र ने दे भी दी है।

बहरहाल जलवायु में आ रहे बदलाव के चलते यह तो तय है कि प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। इस लिहाज से ज़रूरी है कि शहरों के पानी का ऐसा प्रबंध किया जाए कि उसका जल भराव नदियों और बांधों में हो, जिससे पानी का उपयोग जल की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में किया जा सके। साथ ही शहरों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। (**स्रोत फीचर्स**)